आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 05.10.2025 समय : 1905

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' अभियान का शुभारंभ किया।
- भारत में छह वर्षों में लगभग सत्रह करोड़ नौकरियां सृजित हुईं। बेरोज़गारी घटकर तीन दशमलव दो प्रतिशत पर पहुंची।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सात से पन्द्रह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क एक वर्ष के लिए माफ किया।
- डाक विभाग की ओर से राष्ट्र स्तरीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है।

<><><><><><><>

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 'आपकी पूंजी आपका अधिकार' अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पचहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस वित्तीय संपत्तियां वापस की जाएंगी। यह अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाला तीन महीने का एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी लोगों से आग्रह की है कि इस अभियान के अम्बेसडर बनकर, अपने समुदायों और आस–पास के इलाकों में इस अभियान के बारे में प्रचार करें।" वित्त मंत्रालय, नियामकों, राज्य सरकारों और गांवों के बैंकों सहित सभी के सम्मिलित प्रयासों से अगर पूरी श्रृंखला सक्रिय हो जाए, तो हर कोई अपना पैसा वापस पा सकेगा। इस अभियान के दौरान, नागरिकों को उनके अनक्लेम्ड एसेट्स, अपडेट रिकॉर्ड, क्लेम प्रक्रिया को पूरा करने के तरीकों को लेकर तत्काल मार्गदर्शन किया जाएगा।

<><><><><><><>

देश में पिछले छह वर्षों में लगभग सत्रह करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं। श्रम और रोज़गार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष दो हजार सत्रह–अटठारह में में सैंतालीस करोड़ पचास लाख रोजगार सृजन हुआ था जो वर्ष दो हजार तेईस–चौबीस में बढ़कर चौसठ करोड़ तैंतीस लाख हो गया। इसके अलावा, बेरोज़गारी दर वर्ष दो हजार सत्रह–अटठारह में छह प्रतिशत से घटकर दो हजार तेईस–चौबीस में तीन दशमलव दो प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में युवा बेरोज़गारी दर भी सत्रह दशमलव आठ प्रतिशत से घटकर दस दशमलव दो प्रतिशत हो गई है। इस बीच, महिलाओं के कार्यबल में भी वृद्धि हुई है और पिछले सात वर्षों में एक करोड़ छप्पन लाख से अधिक महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। वर्ष दो हजार

तेईस–चौबीस में स्व–रोज़गार बढ़कर अटठावन दशमलव चार प्रतिशत हो गया है। मंत्रालय ने इसका श्रेय नवाचारों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को दिया है।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी बचत उत्सव की घोषणा की थी। बाईस सितंबर से शुरू यह उत्सव पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। आज इस कड़ी में पेश है हिमाचल प्रदेश के उद्योगों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव की एक रिपोर्ट–

<><><><><><><><>

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण–यू आई डी ए आई सात से पन्द्रह वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट पहली अक्टूबर से लागू हो गई है और एक वर्ष के लिए लागू रहेगी। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार नामांकन के लिए नाम, फोटो, जन्मतिथि, लिंग और पता जैसे केवल मूल जन–सांख्यिकीय विवरण की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के विकास कारकों के कारण उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें उंगलियों के निशान, आईरिस और अपडेट की गई तस्वीरें शामिल हैं, बच्चे के पाँच वर्ष का होने पर आवश्यक होता है। दूसरा अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बच्चे के पन्द्रह वर्ष का होने पर आवश्यक होता है। पांच से सात और पन्द्रह से सत्रह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पहला और दूसरा आधार बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क है। इसके बाद, प्रत्येक आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए एक सौ पच्चीस रुपये का निर्धारित शुल्क लिया जाता है।

<><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान ज़िला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी ने एक दल के साथ मंगलूटन, लाइनड़ेरा, मंजरी और लोहा बैरिक में नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्थलों का निरीक्षण किया। भूमि की पहचान कर ली गई है। दल ने गुप्तापाड़ा और वांडूर जेटी के आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति देखी तथा बंद केंद्रों को शीघ्र चालू करने के निर्देश दिए। सभी केंद्रों में शौचालय, रसोईघर, जलापूर्ति और खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। साथ ही, वांडूर जेट्टी व मंगलूटन स्थित कृषि डिपो के जर्जर भवनों के सुधार के लिए भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

<><><><><><><><>

डाक विभाग की ओर से राष्ट्र स्तरीय ढाई आखर पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 8 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसका विषय है "मेरे आदर्श को पत्र"। पत्र अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी स्थानीय भाषा में लिखा जा सकता है, जिसकी अधिकतक सीमा सादे कागज़ पर, अधिकतम 1000 शब्द और अंतर्देशीय पत्र कार्ड पर 500 शब्द है। प्रतियोगिता में केवल हस्तलिखित पत्र ही स्वीकार किए जाएँगे। प्रविष्टियां केवल उभरे हुए लिफाफे या डाक टिकट लगे लिफाफे और अंतर्देशीय पत्र कार्ड में ही स्वीकार्य होंगे। इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। द्वीपसमूह के प्रतिभागियों का चयन पश्चिम बंगाल मंडल द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक मंडल हर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ तीन प्रविष्टियां का चयन करेगा और इन प्रविष्टियों को परिमंडल स्तर पर नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएँगे। इन चुनी गई प्रविष्टियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, जहाँ प्रत्येक श्रेणी में शीर्ष तीन प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पत्र "मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल मंडल, कोलकाता" के पते पर भेजे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए पोस्टमास्टर जनरल कार्यालय, से फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस द्वारा आयोजित "एस.पी. कप फुटबॉल टूर्नामेंट –दो हजार पच्चीस" का समापन मायाबंदर के नेताजी स्टेडियम में हुआ। "नशा मुक्त भारत" थीम पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना था। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक श्वेता के. गुप्ता मुख्य अतिथि थीं। फाइनल मुकाबले में दिव्यांका–एन.एफ.सी. ने बकुलतला–एफ.सी. को हराकर ट्रॉफी जीती। विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का समापन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक के साथ हुआ, जिसमें लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया।

<><><><><><><>

भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज मध्य प्रदेश के उज्जैन, में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव सोनी ने की। बैठक में अटठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जयदीप कुमार डे, और राष्ट्रीय सचिव एस. बीजू पिल्लई को महाकाल की प्रतिमा और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बैठक में विभिन्न राज्यों के विभिन्न एजेंडों और केंद्र सरकार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

<><><><><><><>